

कानूनी क्षेत्र में बदलाव: कृत्रिम रूप से बदलना और कानून का संगम

Asha Singh^{1*}, Mangi Lal² and Dr. Manoj Kumar Dhaniya³

¹Department of Commerce and Management, Nirwan University, Jaipur, Rajasthan, India
Email: ashanikitha@gmail.com; *Corresponding Author; Orcid ID: 0000-0002-4184-6593

²Department of Law, Jayoti Vidyapeeth University, Jaipur, Rajasthan, India
Email: mangibjp@gmail.com

³SBS Degree College Sabalpara, Sikar, Rajasthan, India.
Email: univ9edu@gmail.com

अमूर्त

पिछले दस सालों में, लीगल सेक्टर में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं, का इस्तेमाल कई तरह की लीगल एक्टिविटीज़, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, लीगल रिसर्च और केस के नतीजों का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। कानून में AI का इस्तेमाल प्राइवसी, बायस और ज़िम्मेदारी के सवाल खड़े करता है, जबकि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और खर्च कम करने की क्षमता है। इस रिसर्च पेपर में AI और लीगल सेक्टर में इसके इस्तेमाल का एक ओवरव्यू दिया गया है। यह निबंध लीगल सिस्टम में AI को अपनाने के नैतिक और कानूनी असर के साथ-साथ ऐसा करने के फायदे और मुश्किलों पर भी बात करता है। स्टडी यह भी देखती है कि AI लीगल प्रोफेशन और वकीलों के काम के भविष्य को कैसे बदल सकता है। यह पेपर रिसर्चर्स, वकीलों और लेजिस्लेटर्स के लिए सुझावों के साथ खत्म होता है कि AI के रिस्क को कम करते हुए इसके प्रॉमिस को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। इसलिए, अब यह ज़रूरी है कि हर ज़रूरी इनोवेशन सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल और जस्टिफाइड दोनों हो। लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल से कॉस्ट कम करने, जस्टिस तक पहुंच बढ़ाने और लीगल सर्विसेज़ की कैलिबर को बढ़ाने की क्षमता है। फिर भी, लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक और कानूनी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। आने वाले सालों में, शायद लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल को सीमित करने वाले और भी कानून और नियम होंगे, क्योंकि भारत सरकार इस बारे में कार्रवाई कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यह शुरू में ही असल दुनिया की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकता है। AI का इस्तेमाल कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जिसमें मैनुफैक्चरिंग, बिज़नेस और हेल्थकेयर शामिल हैं। इन फील्ड्स में AI की ज़बरदस्त ग्रोथ को देखते हुए, लीगल सिस्टम में सिर्फ शामिल होने से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। कई लॉ कंपनियाँ आज भी नए ज़माने के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहती हैं। ज़्यादा प्रोडक्टिव और कुशल होने के लिए, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ और इस्तेमाल करना पसंद करेंगी। AI बार-बार होने वाले काम करके वकीलों का समय दूसरी ज़रूरी और स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ के लिए खाली करता है। यह पेपर बताता है कि AI लॉ एनफोर्समेंट की असर और एफिशिएंसी को कैसे बेहतर बना सकता है। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी आगे बढ़ गया है। बहुत से लोग चैटबॉट के आदी हो गए हैं, और Google, Alexa और Siri जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की पीढ़ी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमाल की तरक्की देखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के कई बिज़नेस में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है, और सिरी, एलेक्सा और गूगल जैसे वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। आखिर में, यह लेख इस बात की जांच करता है कि AI भविष्य में कानूनी क्षेत्र को कैसे प्रभावित और बदलता रहेगा।

कीवर्ड : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), वकील, मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), गोपनीयता और पूर्वाग्रह।

परिचय

मुश्किल मामलों के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कई इंडस्ट्रीज़ को बदल रहा है। यह लीगल सेक्टर पर भी लागू होता है। AI में लीगल इंडस्ट्री में कई तरह से क्रांति लाने की क्षमता है, जिसमें लीगल एनालिसिस की सटीकता को बेहतर बनाना से लेकर बार-बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करना शामिल है। लीगल सेक्टर में AI का इस्तेमाल पहले ही बढ़ना शुरू हो गया है, और इसमें ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानून के बीच के रिश्ते की जांच करता है, जिसमें लीगल सेक्टर में इसके कई इस्तेमाल, इसके नैतिक असर और इसकी संभावनाएं शामिल हैं।

डिजिटल क्रांति जिसने कई इकोनॉमिक सेक्टर को बदल दिया है, सिर्फ लीगल फील्ड तक ही सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लीगल काम को ऑटोमेट करके और लीगल प्रोसीजर को असरदार बनाकर लीगल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलने की क्षमता है। कंप्यूटर विज्ञान, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसी AI टेक्नोलॉजी की वजह से लीगल फील्ड पहले से ही बदल रहा है। AI से चलने वाली टेक्नोलॉजी अब कॉन्ट्रैक्ट ड्रैफ्टिंग, लीगल रिसर्च, और केस के नतीजे का अनुमान लगाने जैसे काम कर सकती हैं जो पहले सिर्फ वकील ही करते थे।

हालांकि लीगल सेक्टर में AI अभी भी काफी नया है, लेकिन इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के एक एनालिसिस में दुनिया भर के लीगल AI मार्केट का साइज़ \$714.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। 2020 में और 2021 से 2028 के बीच 37.9% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है (ग्रैंड व्यू रिसर्च, 2021)। रिसर्च में इस डेवलपमेंट के कारणों के तौर पर असरदार कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत, बढ़ती कानूनी लागत और कानूनी प्रक्रियाओं में ऑटोमेशन की बढ़ती मांग का ज़िक्र किया गया है।

इंसान अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करके कैसे महसूस करते हैं, सीखते हैं, तर्क करते हैं और काम करते हैं, उससे प्रेरित होकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है। इन नई टेक्नोलॉजी से कई इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, लेकिन चिंता है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है या इन्हें अचानक और खतरनाक तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

कानून में AI का इस्तेमाल प्राइवसी, भेदभाव और ज़िम्मेदारी के सवाल खड़े करता है, जबकि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और खर्च कम करने की क्षमता है। लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल को लेकर नैतिक और कानूनी चिंताएँ हैं। उदाहरण के लिए, हम AI सिस्टम की जवाबदेही और पारदर्शिता की गारंटी कैसे दे सकते हैं? AI से फैसले लेने में भेदभाव से कैसे बचा जा सकता है? ऐसी दुनिया में जब AI कानूनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल सकता है, तो वकीलों की क्या भूमिका होती है? इस रिसर्च रिपोर्ट का मकसद इनमें से कुछ समस्याओं का जवाब देना है।

इस रिसर्च पेपर में AI और लीगल सेक्टर में इसके इस्तेमाल का एक ओवरव्यू दिया गया है। यह निबंध लीगल सिस्टम में AI को अपनाने के नैतिक और कानूनी असर के साथ-साथ ऐसा करने के फायदे और मुश्किलों के बारे में बताता है। स्टडी यह भी देखती है कि AI लीगल प्रोफेशन के भविष्य और वकीलों के काम को कैसे बदल सकता है। यह पेपर रिसर्चर्स, वकीलों और लेजिस्लेटर्स के लिए सुझावों के साथ खत्म होता है कि AI के रिस्क को कम करते हुए इसके प्रॉमिस को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से लीगल सेक्टर में कई बदलाव हो सकते हैं। लीगल सेक्टर में AI का इस्तेमाल पहले ही बढ़ना शुरू हो गया है, जिसमें भविष्य में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें बार-बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करने से लेकर लीगल एनालिसिस की सटीकता को बेहतर बनाने तक शामिल है। यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानून के बीच के रिश्ते की जांच करता है, जिसमें लीगल सेक्टर में इसके कई इस्तेमाल, इसके नैतिक असर और इसकी संभावनाएं शामिल हैं।

क्योंकि लीगल इंडस्ट्री को अभी भी मेहनत वाला माना जाता है, इसलिए इंडियन लीगल प्रोफेशन के नेचर की वजह से पूरा प्रोसेस मैनुअली किया जाता है। इस वजह से, AI अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, और कई पुराने सपोर्ट्स को लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए क्योंकि यह किसी दिन इंसानों की जगह ले सकती है। इस वजह से, कानून में AI के कॉन्सेप्ट से बचा जाता है। फिर भी, कई टेक-सैवी वकील और बड़ी लॉ फर्म अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने के लिए टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रही हैं। यह बात सभी जानते हैं क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम बहुत बड़ा है, अकेले हमारा संविधान दुनिया में सबसे लंबा है; इसलिए, बदलते हालात के हिसाब से कानून में AI का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कुछ ही सेकंड में, वकील लीगल रिसर्च में मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लीगल दुनिया के बारे में बेमिसाल जानकारी पा सकते हैं। एक कंपनी जिसने AI का पोर्टेंशियल देखा है और एक्टिवली इसका इस्तेमाल कर रही है, वह है सिरिल आर्मरचंद और मंगलदास। कनाडा में किरा सिस्टम्स द्वारा बनाई गई मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी "किरा" को लाइसेंस देने वाली पहली इंडियन लीगल फर्म के तौर पर, CAM ने इतिहास रच दिया है। इस AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर से कई काम किए जा सकते हैं, जिससे बहुत समय और मेहनत बचती है। "किरा" टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग-अलग कानूनी डॉक्यूमेंट्स से नियम निकालने, किसी भी खतरनाक जगह का पता लगाने और पहचानने, और कानूनी डॉक्यूमेंट्स को जांचने के लिए किया जाता है।

भारत में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कानूनी सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। AI का इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने, कामकाज को बेहतर बनाने और प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन कोर्ट सिस्टम में AI के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारी नैतिक और कानूनी चिंताएं भी हैं।

खास कैटेगरी के लोगों को बाहर करने के लिए AI का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, यह एक गंभीर चिंता की बात है। उदाहरण के लिए, AI-पावर्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि कौन नौकरी या लोन के लिए एलिजिबल है, जिसका खास डेमोग्राफिक्स पर असर पड़ सकता है।

AI से लोगों की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, यह एक और चिंता की बात है। AI से चलने वाले सिस्टम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, जिसका इस्तेमाल लोगों की आदतों, पसंद और मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से लोग अपनी प्राइवेसी खो सकते हैं और अपने डेटा पर उनका कंट्रोल कम हो सकता है। आखिर में, यह भी चिंता है कि AI के फैसले लोगों के भले के लिए न हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम का इस्तेमाल कई तरह की इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट और एडवर्टाइजिंग शामिल हैं, क्योंकि वे ज़रूरी नतीजे निकालने और डेटा को क्लासिफ़ाई और कैटेगरीज़ करने में सक्षम हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों तरह से प्राइवेसी और एनोनिमिटी की हमारी उम्मीदें, उनके इस्तेमाल से मुमकिन हुई प्रोफ़ाइलिंग से काफ़ी बदल जाती हैं। AI सिस्टम की डेटा से जानकारी निकालने, पैटर्न पहचानने और ट्रेंड का अनुमान लगाने की क्षमता की वजह से, नुकसान न पहुँचाने वाली जानकारी को भी काम का और करीबी बनाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, AI-पावर्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित पार्टियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखे बिना रिसोर्स कैसे बांटे जाएं। कानून लागू करने में AI के इस्तेमाल से जुड़ी नैतिक और कानूनी चिंताओं को भारत सरकार मानती है। सरकार ने 2018 में जो नेशनल AI स्ट्रेटजी पब्लिश की थी, उसमें AI के इस्तेमाल और काम को बढ़ाने के लिए कई गाइडलाइंस दी गई हैं। इन गाइडलाइंस में लोगों के प्राइवेसी के अधिकार

की सुरक्षा करना, यह पक्का करना कि AI का इस्तेमाल सही और बराबर तरीके से हो, और यह पक्का करना कि AI का इस्तेमाल मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए हो, शामिल हैं।

लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए, सरकार खास नियम और कानून भी बना रही है। पर्सनल डेटा इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने और शेयर करने के लिए सरकार ने 2020 में एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। इस कानून में कानूनी वजहों से AI के इस्तेमाल के बारे में डिटेल में बताया गया है। AI में कानून लागू करने के तरीके को बदलने की क्षमता है, भले ही कानून लागू करने में इसका इस्तेमाल अभी शुरुआती स्टेज में है। आने वाले सालों में, लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल से जुड़े नए कानून और नियम भारत सरकार लागू करेगी, जो यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही और ज़िम्मेदारी से किया जाए।

साहित्य की समीक्षा

वैश्विक विकास: ऐतिहासिक

रिसर्चर्स ने 1970 के दशक में कानूनी तर्क और फैसले लेने को ऑटोमेट करने के लिए AI का इस्तेमाल करने की संभावना पर गौर करना शुरू किया, तभी AI और कानून का इतिहास शुरू हुआ। नियम-आधारित सिस्टम पर ज़ोर, जो चुनाव करने के लिए साफ तौर पर कोड किए गए नियमों पर निर्भर थे, AI और कानून के शुरुआती सालों की एक खास बात थी।

MYCIN, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1970 के दशक की शुरुआत में बनाया गया एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, जो पहले और सबसे ज़रूरी सिस्टम में से एक था। MYCIN को फैलने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि AI का इस्तेमाल कम और साफ़ न होने वाली जानकारी के साथ तर्क करने के लिए कैसे किया जा सकता है – जो कानूनी तर्क में एक बड़ी समस्या है।

रिसर्चर्स ने 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में कानूनी एप्लीकेशन, जैसे डॉक्यूमेंट रिव्यू और केस-बेस्ड रीज़निंग में AI के इस्तेमाल पर गौर करना शुरू किया। दोनों फील्ड के रिसर्चर्स और प्रैक्टीशनर्स 1987 में पहली AI और लॉ कॉन्फ्रेंस में कानून में AI के पोटेंशियल के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए।

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और लीगल एक्सपर्ट सिस्टम, कानून में AI के कुछ नए इस्तेमाल हैं जो 1990 और 2000 के दशक में सामने आए। 1990 के दशक के आखिर में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के बढ़ने से बड़े पैमाने पर कानूनी जानकारी का आधार बनाना मुमकिन हुआ, जो कानूनी फैसले लेने में मदद कर सकता था।

कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, ई-डिस्कवरी और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स में इस्तेमाल होने के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल के सालों में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और आम हो गया है। लीगल टेक्नोलॉजी बिज़नेस ने लीगल प्रोफेशनल्स के लिए AI-बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप और मार्केट किए हैं, और कई लॉ फर्म और लीगल डिपार्टमेंट ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए इन टेक्नोलॉजी को लागू करना शुरू कर दिया है।

इन डेवलपमेंट के बावजूद, कानून में AI का इस्तेमाल अभी भी बहस का मुद्दा है और इसमें कई कानूनी और नैतिक मुद्दे हैं। उम्मीद है कि अगर AI और डेवलप होता है, तो AI और कानून के बीच का लिंक भी मजबूत होगा।

कानून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूदा स्थिति

लगभग \$1 ट्रिलियन की ग्लोबल मार्केट वैल्यू के साथ, लीगल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। हालाँकि, यह अभी भी डिजिटल नहीं है। अच्छा हो या बुरा, वकील समय के साथ बने सॉल्यूशन पर ही भरोसा करते हैं क्योंकि लीगल प्रोफेशन नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में कल्चरल और बदनाम रूप से धीमा है। आने वाले सालों में, यह बदल सकता है। AI में आम लोगों के भारतीय कानून को देखने के तरीके और लीगल प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके, दोनों को बदलने

की क्षमता है। यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लीगल रिसर्च उन सबसे ज़रूरी एरिया में से एक है जहाँ AI असर डाल सकता है। भारतीय लीगल सिस्टम के डायनामिक कैरेक्टर की वजह से, वकील अपनी चालाक स्किल्स का इस्तेमाल करके कानून की एक यूनिक समझ जल्दी हासिल कर सकते हैं। AI कालिटी से समझौता किए बिना लीगल रिसर्च की कीमत को मैच कर सकता है। यह वकीलों को उनके क्लाइंट्स को बेहतर सलाह देने में मदद करने के लिए मददगार रिसोर्स दे सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से लीगल फील्ड तेज़ी से बदल रहा है। AI का इस्तेमाल स्मार्ट फैसले लेने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन लीगल सिस्टम में AI के इस्तेमाल से कई नैतिक और कानूनी दिक्कतें भी हैं। आजकल, आजकल की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादातर सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हैं। हालांकि, लीगल एरिया में आजकल की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ने के लिए, उन्हें अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी और फाइल-हैंडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करना होगा। इसलिए, वकीलों को आजकल की टेक्नोलॉजी से परिचित होने की बहुत ज़रूरत है। इस स्थिति में, वे अपनी तरक्की का असर बढ़ाने के लिए आसानी से AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा, ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन के लिए इन सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्मार्ट असिस्टेंट से लेकर मोबाइल डिवाइस पर ऑटोकरेक्ट टेक्नोलॉजी तक AI एप्लिकेशन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इसे डेमोक्रेसी का एक ज़रूरी हिस्सा माना है और पाया है कि इस आज़ादी में जानने का अधिकार भी शामिल है।¹⁷⁸ AI का बोलने की आज़ादी पर बड़ा असर पड़ता है।

कानूनी क्षेत्र में एआई

उपयोग और लाभ

लीगल सेक्टर में AI टेक्नोलॉजी के कई इस्तेमाल हैं, जिसमें कंप्यूटर विज़न, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग टेक्नीक शामिल हैं। लीगल फील्ड में AI के कुछ सबसे पॉपुलर इस्तेमाल नीचे दिए गए हैं:

कानूनी जांच

बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना और एनालाइज़ करना लीगल स्टडी का एक टाइम लेने वाला हिस्सा है। वकील लेक्सिसनेक्सिस, वेस्टलॉ और ब्लूमबर्ग लॉ जैसे AI-पावर्ड रिसोर्स की मदद से लीगल रिसर्च ज़्यादा असरदार तरीके से कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके लीगल पेपर्स को एनालाइज़ करती हैं और ज़रूरी जानकारी निकालती हैं। इससे वकीलों के लिए ज़रूरी केस, कानून और रेगुलेशन ढूँढना आसान और तेज़ हो जाता है।

लीगल रिसर्च, लीगल सेक्टर में AI के मुख्य इस्तेमाल में से एक है। पहले, लीगल एनालिसिस के लिए ज़रूरी फैक्ट्स ढूँढने के लिए केस लॉ और लीगल डेटाबेस में मैनुअली सर्च करना पड़ता था। लॉ फर्म के लिए, इस प्रोसेस में घंटों या दिन भी लग सकते हैं, जिससे यह महंगा और टाइम लेने वाला काम बन जाता है। ज़्यादा सटीक और अच्छे रिज़ल्ट देकर, Westlaw, Fast Case, और LexisNexis जैसे AI-पावर्ड लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म ने लीगल रिसर्च प्रोसेस में क्रांति ला दी है।

AI-पावर्ड लीगल रिसर्च टूल्स, लीगल मटीरियल को एनालाइज़ करने और ज़रूरी कानूनों और केस को खोजने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स सर्च क्वेरी के आधार पर सबसे ज़रूरी टॉपिक को तेज़ी से पहचानकर लीगल रिसर्च की एक्ज़्यूरेसी को तेज़ और बेहतर बनाते हैं। AI-पावर्ड लीगल रिसर्च टूल्स कानूनी मिसाल की जानकारी भी दे सकते हैं, जिससे वकीलों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है।

अनुबंधों का विश्लेषण

कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस कानूनी सेक्टर में AI का एक और इस्तेमाल है। ज़रूरी फ्रेज़ और क्लॉज़ ढूँढने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में कानूनी कागज़ों को देखना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। पहले, कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन एक

समय लेने वाला प्रोसेस था जिसमें वकीलों को हर डॉक्यूमेंट को स्कैन और कन्फर्म करना पड़ता था। यह प्रोसेस अब LawGeex और Kira Systems जैसे AI-पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस टूल्स की वजह से ज़्यादा तेज़ और असरदार है।

AI-बेस्ड एनालिटिक्स सिस्टम NLP एल्गोरिदम का इस्तेमाल लीगल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज़ करने और ज़रूरी शब्दों और फ्रेज़ को खोजने के लिए करते हैं। डिस्कलेमर, मैच न करने वाले शब्द, हाइफ़न वाले शब्द, और दूसरे कीवर्ड और फ्रेज़ सभी को इस एप्लिकेशन से तेज़ी से पहचाना जा सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ़्ट करना या मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव के लिए बातचीत करना आसान बनाने के लिए, AI-पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस टूल लीगल डॉक्यूमेंट्स को एवैल्यूएट करके अंतर और समानताओं की पहचान भी कर सकते हैं।

दस्तावेजों की समीक्षा

हाल के सालों में डॉक्यूमेंट असेसमेंट में AI टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ी है। AI:

पावरफुल डॉक्यूमेंट रिव्यू सिस्टम से बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स को तेज़ी से एनालाइज़ किया जा सकता है ताकि नाम, तारीखें और काम के कीवर्ड जैसी ज़रूरी जानकारी मिल सके। ये टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड में किसी भी समस्या या अंतर का भी पता लगा सकती हैं, जैसे डेटा का गायब होना या जानकारी का उलटा होना। लीगल प्रोफ़ेशनल AI-पावर्ड डॉक्यूमेंट रिव्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट रिव्यू का समय और खर्च काफी कम हो सकता है।

विश्लेषणात्मक भविष्यसूचक

प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स लीगल सेक्टर में AI का एक और इस्तेमाल है। भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए डेटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स कहलाता है। प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल लीगल इंडस्ट्री में केस के नतीजों का अनुमान लगाने, संभावित खतरों का पता लगाने और लीगल स्ट्रेटेजी के सुझाव देने के लिए किया जा सकता है।

जब प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स की बात आती है, तो लीगल सेक्टर में AI टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है। भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए डेटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स कहलाता है। प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल लीगल इंडस्ट्री में केस के नतीजों का अनुमान लगाने, संभावित खतरों का पता लगाने और लीगल स्ट्रेटेजी के सुझाव देने के लिए किया जा सकता है। AI-ड्रिवन प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम, जिसमें ब्लू जे लीगल और प्रीमोनिसन शामिल हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके केस लॉ का एनालिसिस करते हैं और कोर्ट के फैसलों का अनुमान लगाते हैं। ये रिसोर्स वकीलों को बेहतर फैसले लेने और किसी टॉपिक के संभावित नतीजे के बारे में जानकारी देकर अपने क्लाइंट को सलाह देने में मदद कर सकते हैं। प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स संभावित खतरों, जैसे रेगुलेटरी कम्प्लायंस से जुड़ी समस्याओं का भी पता लगा सकते हैं, इससे पहले कि वे लीगल मुद्दे बन जाएं।

AI से चलने वाले प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम, जिसमें ब्लू जे लीगल और प्रीमोनिसन शामिल हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके केस लॉ को एनालाइज़ करते हैं और कोर्ट के फैसलों का अनुमान लगाते हैं। ये रिसोर्स किसी टॉपिक के अनुमानित असर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे वकील बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने क्लाइंट को सलाह दे सकते हैं। प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स संभावित खतरों, जैसे रेगुलेटरी कम्प्लायंस से जुड़ी समस्याओं को भी कानूनी मुद्दे बनने से पहले पहचान सकते हैं।

कानूनी जांच

लीगल रिसर्च, लीगल सेक्टर में AI के सबसे खास इस्तेमाल में से एक है। AI टेक्नोलॉजी ने वकीलों के लिए लीगल रिसर्च करना आसान और ज़्यादा असरदार बना दिया है, जो लीगल प्रोफ़ेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है। लीगल प्रोफ़ेशनल्स वेस्टलॉ और लेक्सिसनेक्सिस जैसे AI-पावर्ड लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) का इस्तेमाल करके लीगल मटीरियल को एनालाइज़ करते हैं ताकि ज़रूरी कानून, नियम और केस मिल

सर्च। सर्च क्वेरी के आधार पर AI एल्गोरिदम सबसे ज़रूरी चिंताओं की पहचान करते हैं, और ये रिसोर्स लीगल मिसाल की जानकारी देते हैं जो वकीलों को बचाव के लिए सही फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। वकील AI-पावर्ड लीगल रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोफेशन के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं, जो सस्ते होते हैं और लीगल रिसर्च पर लगने वाले समय को कम कर सकते हैं।

पहले, लीगल एनालिसिस के लिए ज़रूरी फैक्ट्स ढूंढने के लिए केस लॉ और लीगल डेटाबेस में मैनुअली सर्च करना पड़ता था। लॉ फर्म के लिए, इस प्रोसेस में घंटों या दिन भी लग सकते थे, जिससे यह महंगा और टाइम लेने वाला काम बन जाता था। ज्यादा सटीक और अच्छे रिज़ल्ट देकर, वेस्टलॉ, फास्ट केस और लेक्सिसनेक्सिस जैसे AI-पावर्ड लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म ने लीगल रिसर्च प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है।

AI-पावर्ड लीगल रिसर्च टूल्स, लीगल मटीरियल को एनालाइज़ करने और ज़रूरी कानूनों और केस को खोजने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स सर्च क्वेरी के आधार पर सबसे ज़रूरी टॉपिक को तेज़ी से पहचानकर लीगल रिसर्च की एक्ज़ुरेसी को तेज़ और बेहतर बनाते हैं। AI-पावर्ड लीगल रिसर्च टूल्स कानूनी मिसाल की जानकारी भी दे सकते हैं, जिससे वकीलों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है।

कानून में AI के कुछ बड़े नुकसानों पर नीचे चर्चा की गई है:

एल्गोरिदम और डेटा पूर्वाग्रह

AI सिस्टम बायस्ड नतीजे दे सकते हैं क्योंकि वे उतने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं जितना डेटा जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। AI एल्गोरिदम को पर्सनल डेटा, जैसे समाज के बायस और पहले के भेदभाव का इस्तेमाल करके ट्रेन किया जा सकता है। अधूरे डेटा से मिले छोटे नतीजों के लीगल सेक्टर में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो AI सिस्टम केस के नतीजों का अनुमान लगाते हैं, वे खास ग्रुप के खिलाफ बायस्ड हो सकते हैं, जिससे गलत नतीजे हो सकते हैं। AI एल्गोरिदम उतने ही निष्पक्ष होते हैं जितना मटीरियल जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है, इसलिए वे शायद तभी काम की जानकारी स्वीकार करें जब वह ज़रूरी चीज़ों के बारे में पिछले विचारों से मेल खाती हो। अगर AI एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए बायस्ड डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वे सीमित हो जाएंगे। इससे लीगल सेक्टर में केस के गलत फैसले हो सकते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल असमानता और बायस बने रह सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, यह पक्का करना ज़रूरी है कि AI एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा निष्पक्ष और रिप्रेजेंटेटिव हो।

प्रतिबंधित दायरा

यह बात कि AI अक्सर सिर्फ कुछ खास कानूनी कामों के लिए ही सही होता है, एक और कानूनी रुकावट है। उदाहरण के लिए, AI से चलने वाले लीगल रिसर्च टूल, ज़रूरी केस लॉ का पता लगाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन, एक इंसानी लीगल रिसर्चर की तुलना में, उन्हें कानूनी मिसाल की बारीकियों को अलग तरह से समझने की ज़रूरत हो सकती है। इसी तरह, AI से चलने वाली डॉक्यूमेंट रिव्यू टेक्नोलॉजी को भी इंसानी रिव्यूअर जितनी ही मुश्किल और डिटेल पहचानने की ज़रूरत हो सकती है, भले ही वे बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज़ करने में बहुत असरदार हों।

संदर्भ का अभाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम सिर्फ उन्हें दिए गए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और वे हमेशा उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाते हैं। कानूनी हालात में, जहाँ किसी शब्द या वाक्य का मतलब खास कानूनी माहौल के आधार पर बदल सकता है, यह खास तौर पर मुश्किल हो सकता है। AI सिस्टम कानूनी कागज़ात को सही तरीके से एनालाइज़ और समझ सकते हैं अगर उन्हें उस कॉन्टेक्स्ट की इंसानी समझ हो।

अपर्याप्त खुलापन

AI एल्गोरिदम के फैसले लेने के प्रोसेस में ज्यादा खुलेपन की ज़रूरत कानून में AI के बड़े नुकसानों में से एक है। AI एल्गोरिदम को अक्सर "ब्लैक बॉक्स" माना जाता है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे किसी खास नतीजे पर कैसे पहुंचे। इस ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण सिस्टम में बायस या गलतियों को ढूंढना और ठीक करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, वकीलों के लिए अपने क्लाइंट्स को किसी खास फैसले के पीछे का कारण बताना मुश्किल हो सकता है।

व्यय और उपलब्धता

AI टेक्नोलॉजी लीगल सेक्टर में खर्च कम कर सकती है, लेकिन इसे लागू करना महंगा हो सकता है। AI टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए कम आसान हो सकती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटी लॉ फर्म और अकेले प्रैक्टिस करने वालों के पास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए फंड नहीं हो सकते हैं। एक्सेस को और भी मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि AI-पावर्ड लीगल सर्विस हर जगह या हर लीगल प्रॉब्लम के लिए नहीं मिलेंगी।

रोजगार का नुकसान

कानून में AI के साथ नौकरी जाने की संभावना एक और बड़ी समस्या है। कई आम काम, जैसे डॉक्यूमेंट रिव्यू और लीगल रिसर्च, AI टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटेड हो सकते हैं, जिससे लीगल सेक्टर में नौकरियों की संख्या कम हो सकती है। AI की वजह से उन लोगों की नौकरी जा सकती है जो रोज़ाना के काम करते हैं, भले ही इससे लीगल प्रोफेशनल्स के पास ज्यादा वैल्यू वाले काम पर ध्यान देने के लिए समय मिल सकता है।

डेटा की सुरक्षा

डेटा ब्रीच और दूसरी सिक्योरिटी दिक्कतों की संभावना, लीगल सेक्टर में AI इस्तेमाल करने का एक बड़ा नुकसान है। सेंसिटिव और प्राइवेट जानकारी लीगल प्रोफेशनल्स संभालते हैं, और किसी भी डेटा ब्रीच के गंभीर फाइनेंशियल और लीगल नतीजे हो सकते हैं। सेंसिटिव डेटा को लीगल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले सही सिक्योरिटी तरीकों और AI टूल्स से सुरक्षित रखना चाहिए।

नैतिक मुद्दे

कानून में AI का इस्तेमाल कई नैतिक मुद्दे उठाता है। उदाहरण के लिए, AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के अपराध करने की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, जो बेगुनाही और प्राइवैसी की धारणा पर सवाल उठाता है। इसी तरह, हायरिंग के फैसलों में AI का इस्तेमाल करने से गलत नतीजे आ सकते हैं। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय, कानूनी क्षेत्र को इन नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए।

COVID-19 के दौरान कानून में AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

COVID-19 महामारी का लीगल सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिससे जजों और वकीलों को काम करने के नए तरीकों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा है। यह बदलाव काफी हद तक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से मुमकिन हुआ है, जो लीगल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और ज़रूरतमंदों को न्याय दिलाते हैं। COVID-19 महामारी के दौरान, लीगल सिस्टम ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इन तरीकों से किया है:

ऑनलाइन सुनवाई। महामारी के दौरान, वर्चुअल सुनवाई का चलन बढ़ गया है, जिससे जज और वकील दूर से सुनवाई कर सकते हैं। इससे कानूनी सिस्टम चलता रहा है और इंफेक्शन का खतरा कम हुआ है।

डॉक्यूमेंट का रिव्यू। AI-पावर्ड डॉक्यूमेंट रिव्यू टेक्नोलॉजी की वजह से वकील अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू ज़्यादा तेज़ी से और असरदार तरीके से कर सकते हैं। मुश्किल मामलों में, जैसे फ़ॉड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में, यह खास तौर पर फायदेमंद साबित हुआ है।

कानूनी जांच। AI से चलने वाले कानूनी रिसर्च टूल्स ने वकीलों के लिए ज़रूरी कानूनों और केस लॉ को ढूँढना आसान और तेज़ कर दिया है। नए या डेवलप हो रहे कानूनी फील्ड से जुड़े केस, जैसे कि COVID-19 से जुड़े केस, को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है।

कानूनी सलाह। कानूनी मामलों पर लोगों को सलाह देने के लिए AI कैपेबिलिटी वाले चैटबॉट इस्तेमाल किए गए हैं। इससे उन लोगों के लिए कानूनी मदद पाना आसान हो गया है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या वकील नहीं रख सकते।

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से COVID-19 महामारी के बीच ज्यूडिशियल सिस्टम काम कर पाया है। इसके अलावा, इससे ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी सेवाएं ज़्यादा आसानी से मिल पाई हैं। जैसे-जैसे महामारी फैलेगी, कोर्ट सिस्टम में AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शायद और बड़े पैमाने पर होगा।

जस्टिस सिखरी के मुताबिक, "लॉकडाउन की वजह से इंसाफ़ के पहिये नहीं रुक सकते।" COVID-19 महामारी के दौरान इंसाफ़ दिलाने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट कॉस्ट पेमेंट शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो "ई-रूम" नाम के पूरी तरह से पेपरलेस कोर्टरूम भी बनाए हैं, जहाँ क्लाइंट अपने केस की डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ही वह दोस्त है जो हम सभी की मुश्किलों में बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। इसलिए, अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की को अपनाया जाए और आगे बढ़ते रहें।

अनुसंधान अंतराल

कई संबंधित AI टेक्नोलॉजी को कानूनी और AI क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

LLM के आने से कानून बनाने और उसके मैनेजमेंट में मदद करने के मौके बढ़े हैं। यह लेख कानूनी LLM का पहला पूरा एनालिसिस देता है, जिसमें उनकी परिभाषा, महत्व, इस्तेमाल और उम्मीदें शामिल हैं। हम अपने पेपर में मुख्य रूप से इन तीन सवालों पर बात करते हैं:

- भविष्य में AI और कानून कैसे विकसित होंगे?
- लीगल LLM में क्या खूबियां होती हैं, और उनमें क्या कमियां होती हैं?
- क्या लीगल सिस्टम में जजों की जगह लेना मुमकिन है?
- इसके अलावा, हम लीगल LLM को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं।

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियां देना मुमकिन है? - कानूनी एक्सपर्ट और फ़ैसले लेने वाले इस मुश्किल विषय पर बहस करते रहते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियां दी जा सकती हैं। AI12 को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियां देने के कई कारण हैं।

एक दावा यह है कि AI ज़्यादा एडवांस हो रहा है और ऐसे फ़ैसले लेने में सक्षम है जिनका लोगों की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसे लोन या नौकरी मिलेगी, यह फ़ैसला अब AI-पावर्ड एल्गोरिदम से लिया जाता है, और ये फ़ैसले लोगों की फ़ाइनेंशियल और आर्थिक सेहत पर काफ़ी असर डाल सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि AI को

अपने कामों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और अगर वह इस तरह के फैसले ले रहा है तो उसके पास इंसानों जैसे ही अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए।

AI को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ देना इस बात से भी सही है कि यह इंसानों को AI के संभावित खतरों से बचाएगा। उदाहरण के लिए, अगर AI का इस्तेमाल ऑटोनॉमस हथियार सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है, तो यह पक्का करने के लिए सटीक कानून और गाइडलाइन होना ज़रूरी है कि इन हथियार सिस्टम का इस्तेमाल ऐसे तरीके से न किया जाए जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। अगर AI के पास कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ होतीं, तो यह गारंटी देना आसान होता कि इन हथियार सिस्टम का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी और नैतिक रूप से किया जाए।

फिर भी, AI को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ देने पर कई आपत्तियाँ हैं।

एक तर्क यह है कि AI में इंसानी नैतिक दर्जा नहीं है और वह कोई इंसान नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो, AI सिस्टम ऐसी मशीनें हैं जिन्हें खास काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्हें इंसानों की तरह अपने काम के लिए नैतिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनमें इंसानी सोच, भावना और अनुभव की कमी होती है।

AI को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ देने के खिलाफ़ एक और तर्क यह है कि ऐसा करना रिस्की होगा। अगर AI को लोगों के जैसे ही अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, तो यह इंसानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर AI को प्रॉपर्टी रखने की काबिलियत दी जाती है, तो वह अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा, अगर AI को वोट देने की काबिलियत दी जाती है, तो वह ऐसे नेताओं को सपोर्ट कर सकता है जो लोगों के लिए नुकसानदायक होंगे।

आखिर में, यह तय करना मुश्किल है कि AI को कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ दी जाएं या नहीं, यह हर किसी को अपने हिसाब से तय करना होगा। इस बहस के दोनों तरफ़ मज़बूत तर्क हैं, और इसका कोई आसान हल नहीं है।

तरीकों

ITE से जुड़ा 2016 का लॉ नंबर 16, पर्सनल डेटा की सुरक्षा से जुड़ा 2022 का लॉ नंबर 27, और रिसर्च के मुद्दे से जुड़े दूसरे कानूनों और नियमों का इस्तेमाल इस काम में नॉर्मेटिव लीगल रिसर्च के उदाहरण के तौर पर किया गया, जो लाइब्रेरी से मिले सेकेंडरी सबूतों का आकलन करता है। इसके अलावा, यह स्टडी कई पुराने रिसर्च सोर्स से ली गई है, जिसमें किताबें, लीगल जर्नल और दूसरे ज़रूरी पेपर शामिल हैं। इस स्टडी में इस्तेमाल किए गए लीगल अप्रोच की कैटेगरी में कानूनी तरीके, कॉन्सेप्चुअल तरीके और तुलनात्मक कानूनी तरीके शामिल हैं। यह रिपोर्ट इंडोनेशिया के AI नियमों के डेवलपमेंट की तुलना रूस, US, EU और चीन के नियमों से भी करती है। लाइब्रेरी रिसर्च से इकट्ठा किए गए सभी लीगल मटीरियल को कैटेगरीज़ किया जाएगा, तरीके से ऑर्गनाइज़ किया जाएगा, और इंटरप्रीटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाएगा। बाद में डेटा से नतीजे निकालकर मुश्किलों को हल किया जाएगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, AI और कानून के क्षेत्र में लीगल सेक्टर को काफी बदलने की क्षमता है। AI टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कई तरह के कानूनी कामों में सटीक, कुशल और किफायती साबित हुआ है। कानूनी पेशेवर डॉक्यूमेंट की जांच, केस एनालिसिस और फैसले लेने के लिए AI एल्गोरिदम से फायदा उठा सकते हैं।

लेकिन, लीगल सेक्टर में AI के इस्तेमाल से कई नैतिक और कानूनी दिक्कतें हैं। जब AI का इस्तेमाल फैसले लेने के प्रोसेस में किया जाता है, तो अकाउंटैबिलिटी, ओपननेस और ड्यू प्रोसेस जैसे बेसिक कानूनी कॉन्सेप्ट का उल्लंघन हो सकता है। AI की वजह से कुछ खास लोगों या ग्रुप के खिलाफ भेदभाव और एकतरफ़ा नतीजे निकल सकते हैं।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए कानूनी जानकारों और कानून बनाने वालों को यह पक्का करना होगा कि AI सिस्टम ज़्यादा ज़वाबदेह, ट्रांसपेरेंट हों और नैतिक और कानूनी ज़रूरतों का पालन करें। किसी भी भेदभाव या गलती को ढूँढने और ठीक करने के लिए, उन्हें यह भी पक्का करना होगा कि AI सिस्टम का ऑडिट और असेसमेंट हो।

सब बातों को ध्यान में रखते हुए, AI में खर्च कम करने और लीगल सेक्टर के असर और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की काबिलियत है। अचानक होने वाले नतीजों को रोकने के लिए, यह पक्का करना ज़रूरी है कि AI सिस्टम ज़वाबदेह, ट्रांसपेरेंट हों और नैतिक और कानूनी ज़रूरतों का पालन करें। AI में प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, खर्च कम करके और बार-बार होने वाले कामों को आसान बनाकर लीगल सेक्टर को पूरी तरह से बदलने की काबिलियत है। लेकिन कानून में AI को इस्तेमाल करने के साथ कुछ ज़रूरी प्रैक्टिकल और नैतिक मुद्दे भी हैं। लीगल प्रैक्टीशनर्स को अपने काम में AI टेक्नोलॉजी को शामिल करने के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि वे इसे नैतिक और ज़िम्मेदार तरीके से करें। AI टेक्नोलॉजी, इसके इस्तेमाल में आने वाली मुश्किलों के बावजूद, एक ज़्यादा असरदार और कुशल ज्यूडिशियल सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद कर सकती है।

AI और कानून के बीच का रिश्ता तेज़ी से ज़रूरी होता जा रहा है। कानूनी एप्लीकेशन में AI में लीगल सेक्टर को पूरी तरह से बदलने और कानूनी सेवाओं तक क्लाइंट की पहुँच और उनकी कुशलता को बेहतर बनाने की क्षमता है। लेकिन कानून में AI को लागू करने में नैतिक और कानूनी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह ही हल करने की ज़रूरत है।

डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस जैसे बार-बार होने वाले प्रोसेस को ऑटोमेट करना कानूनी फील्ड में AI के मुख्य फायदों में से एक है। इसके नतीजे में कानूनी सर्विस ज़्यादा सस्ती और टाइम-एफिशिएंट हो सकती हैं, जिससे लोगों और छोटे बिज़नेस दोनों के लिए उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत सारे डेटा के आधार पर ज़्यादा सटीक फोरकास्ट और इनसाइट्स देकर, AI कानूनी फैसले लेने को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

ज़्यादातर वकीलों को अभी भी आजकल की टेक्नोलॉजी के फीचर्स का इस्तेमाल किए बिना अपने कॉन्ट्रैक्टिंग और डॉक्यूमेंट्री असाइनमेंट पर काम शुरू करने की ज़रूरत है। अपनी तरक्की के दौरान, वे हार्ड फाइल और शीट का इस्तेमाल करते रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर, कम से कम, असली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह, सिर्फ़ इंसानी वकील ही "रीज़निंग और आर्गुमेंट" कर सकते हैं। हालांकि, एक बेहतर AI वकील सबूतों को तेज़ी से और अच्छे से क्लासिफ़ाई कर सकता है और सही नतीजे पर पहुँच सकता है। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी डॉक्यूमेंट की जांच करने के लिए भी किया जा सकता है।

लेकिन कानूनी फील्ड में AI का इस्तेमाल करते समय भेदभाव और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी दिक्कतें भी हैं। क्योंकि AI एल्गोरिदम उतने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, जितना डेटा उन्हें ट्रेन किया जाता है, इसलिए अगर इनपुट में पसंद शामिल है, तो वे भेदभाव करेंगे। कुछ लोगों के ग्रुप के लिए, इसका गलत नतीजा हो सकता है। इसके अलावा, कानून में AI का इस्तेमाल अकाउंटैबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर चिंताएं पैदा करता है। जब कोई AI सिस्टम कोई फैसला लेता है, तो यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि यह फैसला कैसे और किसने लिया।

टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से ज्यूडिशियल सिस्टम बदला है। जब आप सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं, तो लीगल प्रोफेशन के भविष्य के बारे में सोचना आसान हो जाता है। आजकल, लीगल काम क्लाइंट पर फोकस होता है।

लीगल रिसर्च करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स बस एक क्लिक दूर होते हैं। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिज़नेस और वकील कॉन्ट्रैक्ट और केस पेपर्स बनाने और उनकी जांच करने के लिए करते हैं।

टूल्स और जानकारी तक एक्सेस देकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वकीलों और छोटी लीगल फर्मों की मदद की है। सर्विसेज़ के मामले में, यह जानी-मानी लॉ कंपनियों के बराबर है। टेक्नोलॉजी की वजह से लीगल प्रैक्टिस का सबसे ज़रूरी हिस्सा लीगल रिसर्च है। CD-ROMs, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और लीगल टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से अखबार और पत्रकार अब अलग तरह से लीगल सर्विसेज़ देते हैं।

टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से बिज़नेस लॉ का फील्ड हमेशा बदल रहा है। यह पाया जा सकता है कि AI के लीगल फील्ड के लिए कई फायदे हैं। जांच में तेज़ी लाने में लीगल प्रोफेशनल्स की मदद करें। गेम के टूल्स से जजों के फैसले लेने में मदद मिल सकती है। यह लॉ फर्मों को डेटा इकट्ठा करने, ड्यू डिलिजेंस और दूसरे कामों में मदद करता है जिससे उनके काम की एफिशिएंसी बेहतर होती है। यह लॉ फर्मों को डेटा इकट्ठा करने, ड्यू डिलिजेंस और दूसरे कामों में मदद करता है जिससे उनके करियर में आगे बढ़ते हैं। AI अपने साफ फायदों के बावजूद वकीलों का रोल नहीं निभा सकता। AI इंसानों जितना क्रिएटिव या लॉजिकल नहीं है, भले ही यह काम के कुछ एरिया में उनकी मदद कर सकता है। रोबोट जज पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनमें समझ या इंटेलिजेंस की कमी होती है। लीगल सेक्टर में AI को इंटीग्रेट करते समय अभी भी बहुत सी रुकावटों को दूर करना बाकी है, जिसमें संभावित खतरे भी शामिल हैं। AI को कंट्रोल करने और डेटा क्लाइंट्स का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क बनाने होंगे। AI से जुड़े खतरों को कम करने के लिए AI एक्शन को डायरेक्ट करने के लिए कानून होने पर ही AI के पूरे फायदे मिल सकते हैं।

सुझाव

1. एक मैनेजमेंट सिस्टम जो इन इंटेलिजेंट मशीनों के काम और काम को ठीक से बताए, उसकी बहुत ज़रूरत थी।
2. इसके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी हिस्से को ध्यान में रखना होगा।
3. प्राइवसी को सुरक्षित रखने के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के कड़े नियम ज़रूरी हैं। इसलिए, इसका जवाब है कि एक कदम पीछे हटें और AI का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, टेक्निकल तरक्की का विरोध करके नहीं, बल्कि इसे अपनाकर और हमारे कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी नियम बनाकर।
4. डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग जैसे कई लीगल सिस्टम के कामों को ऑटोमेट करना। इसके नतीजे में वकील ज़्यादा मुश्किल और स्ट्रेटेजिक काम पर ध्यान दे पाएंगे।
5. डेटा में ट्रेंड और पैटर्न खोजने के लिए। इससे वकीलों को गलतियों से बचने और बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है।
6. कानूनी सेवाओं की कीमत में कमी। जिन लोगों को कानूनी सेवाओं की ज़रूरत है, उन्हें ये आसानी से मिल सकती हैं।
7. AI में कानूनी सलाह देकर लोगों की मदद करने की क्षमता है। जो लोग दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या वकील रखने का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें इसके नतीजे में कानूनी सेवाएं मिलना आसान लग सकता है।

संदर्भ

- ब्रायन्योल्फसन, ई. और मैकाफी, ए. (2017). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असल में. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 1, 1–31.
- कैफारेला, एमजे और एटज़ियोनी, ओ. (2005). नेचुरल लैंग्वेज एप्लीकेशन के लिए एक सर्च इंजन, इन: द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, पेज 442–452.
- काओ, वाई., ली, एस., लियू, वाई., यान, जेड., दाई, वाई., यू, पीएस, सन, एल., एट अल (2023). AI-जेनरेटेड कंटेंट (AIGC) का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे: GAN से ChatGPT तक जेनरेटिव AI का इतिहास। arXiv प्रीप्रिंट, arXiv:2303.04226 .
- कार्लिनी, एन., ट्रेमर, एफ., वालेस, ई., जगिएल्स्की, एम., हर्बर्ट-वॉस, ए., ली, के., रॉबर्ट्स, ए., ब्राउन, टी., सॉंग, डी., एर्लिगसन, यू., एट अल. (2021). बड़े लैंग्वेज मॉडल से ट्रेनिंग डेटा निकालना, 30वें USENIX सिम्योरिटी सिम्पोजियम में, पेज 2633–2650.
- चाल्किडिस, आई., और कैम्पस, डी. (2019). कानून में डीप लर्निंग: बड़े कॉर्पोरा पर शुरुआती अडैप्टेशन और लीगल वर्ड एम्बेडिंग की ट्रेनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानून 27, 171–198.
- चेन, बी., ली, वाई., झांग, एस., लियान, एच., हे, टी., एट अल (2019). न्यायिक निर्णय सहायता के लिए एक डीप लर्निंग विधि, IEEE 19वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सिम्योरिटी कंपेनियन, IEEE में। पेज 145–149.
- चेन, एफ., ली, आर., झांग, एक्स., एट अल (2011). हाईस्पीड डेटा प्रोसेसिंग में फ्लैश मेमोरी बेस्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव के इंटरनल पैरेललिज़्म का फायदा उठाने की ज़रूरी भूमिकाएँ, IEEE 17वें इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, IEEE में। पेज 266–277.
- चेन, एल., चैन, पी., लिन, जेड., एट अल (2020). शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एक समीक्षा. IEEE Access 8, 75264–75278.
- चौधरी, के., और चौधरी, के. (2020). नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल्स, 603–649.
- चर्च, के.डब्लू. (2017). वर्ड2वेक. नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग 23, 155–162.
- कॉन्टिनी, एफ. (2020). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों का बदलाव, न्यायिक कार्यवाही में कानून और टेक्नोलॉजी का इंटरैक्शन। लॉ, टेक्नोलॉजी और इंसान 2, 4–18.
- क्रोटोरू, एफए, होंडरू, वी., इओनेस्कु, आरटी, शाह, एम., एट अल (2023). विज़न में डिफ्यूजन मॉडल: एक सर्वे. IEEE ट्रांजैक्शन ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस, 1–20.
- कुई, जे., ली, जेड., यान, वाई., चैन, बी., युआन, एल., एट अल (2023). चैटलॉ: इंटीग्रेटेड एक्सटर्नल नॉलेज बेस के साथ ओपन-सोर्स लीगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। arXiv प्रीप्रिंट, arXiv:2306.16092 .
- कुई, वाई. (2020). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यूडिशियल मॉडर्नाइजेशन. स्प्रिंगर.
- दास, ए., रैड, पी. (2020). एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (XAI) में मौके और चुनौतियां: एक सर्वे. arXiv प्रीप्रिंट, arXiv:2006.11371.

डे कैपिटानी डि विमेरकाटी, एस., फॉरेस्टी, एस., लिवरागा, जी., समरती, पी. (2012). डेटा प्राइवेसी: परिभाषाएँ और तकनीकें. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ अनसर्टेनिटी, फ़ज़ीनेस एंड नॉलेज-बेस्ड सिस्टम्स 20, 793–817.

डीक्स, ए. (2019). समझाने लायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यायिक मांग. कोलंबिया लॉ रिव्यू 119, 1829–1850.

डेंस्ले, जेए, पायरोज़, डीसी, एट अल (2020). कॉन्टेक्स्ट में मैट्रिक्स: लंदन और उसके बाहर पुलिस गैंग डेटाबेस का जायजा लेना। यूथ जस्टिस 20, 11–30.

डोसिलोविक, एफ.के., ब्रिकिक, एम., हलुपिक, एन., एट अल (2018). एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एक सर्वे, इन: द 41st इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, IEEE. पेज 0210–0215.

डू,एम.,हे,एफ.,ज़ौ,एन., ताओ, डी., हू, एक्स., एट अल (2022). नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की शॉर्टकट लर्निंग: एक सर्वे. arXiv प्रीप्रिंट, arXiv:2208.11857.

एगबर्ट, एस., और क्रासमैन, एस. (2020). प्रेडिक्टिव पुलिसिंग: अभी नहीं, लेकिन जल्द ही प्रीएम्प्टिव? पुलिसिंग और सोसाइटी 30, 905–919.

एली-चुक्कू, NC (2019). खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल: एक रिव्यू. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एप्लाइड साइंस रिसर्च 9.

एटुले, RD, मोसलारेस, FR, पैकड, EZJ, ओडुलो, JL, नैशनल्स, J., क्लैरिडाड, N., और अन्य (2023). कोर्ट में सुनने और ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्मेंस की जांच: फिलीपीन कोर्टरूम में स्टेनोग्राफर के अनुभव। जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैगमैटिक्स स्टडीज 2, 100111.

फगन, एफ., और लेवमोर, एस. (2019). नियमों, स्टैंडर्ड और न्यायिक विवेक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर। सदर्न कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू 93, 1.